भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1813
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

एमटीएनएल का बीएसएनएल में प्रस्तावित विलय

1813. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल की 280 गैर-प्रमुख संपत्तियों में से 220 को साधारण मूल्यांकन पर बेचने के लिए चरणबद्ध तरीके से परिसंपत्ति मुद्रीकरण का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव और मूल्यांकन पर रिपोर्ट और उस पर विशेषज्ञ समिति/मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आज की तारीख में बीएसएनएल की कुल देनदारियां लगभग 23500 करोड़ रुपये और एमटीएनएल की 33,568 करोड़ रुपये हैं, तथा 8000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण चूक हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुद्रीकरण से देनदारियों का भुगतान हो सकता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय करने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ, तो देश भर में एमटीएनएल और बीएसएनएल के पास उपलब्ध अप्रयुक्त संपत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) जी, नहीं महोदय, 280 गैर-प्रमुख संपत्तियों में से 220 संपत्तियों के साधारण मूल्यांकन पर बिक्री का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिनांक 10.7.2025 तक बीएसएनएल पर वर्तमान बकाया ऋण 16,327 करोड़ रुपये है। एमटीएनएल पर बकाया ऋण 34,576 करोड़ रुपये है, जिसमें बैंकों का 8,584 करोड़ रुपये का बकाया ऋण शामिल है।

(घ) मुद्रीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार किया जा रहा है जिसमें ऋण चुकौती भी शामिल है।

(ङ) वर्तमान में, एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय की कोई योजना नहीं है। यद्यपि, सचिव समिति (सीओएस) ने एमटीएनएल के बीएसएनएल में परिचालनात्मक विलय करने की सिफारिश की थी और इस के लिए सरकार ने अनुमोदन प्रदान किया था। इस संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) के बीच हस्ताक्षरित सेवा करार दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी है। मुद्रीकरण के लिए चिन्हित संपत्तियों का अद्यतन विवरण https://assetmonetization.bsnl.co.in पर उपलब्ध है।

*****